जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

(जन–सम्पर्क अनुभाग)

(प्रेस विज्ञप्ति)

विद्युत वितरण निगमों की वीडियों कॉन्फ्रेंस आयोजित

मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान एवं राजस्व वसूली की प्रगति की हुई समीक्षा

सरकारी विभागों पर बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू

जयपुर, 01 मार्च। विद्युत वितरण निगमों के अध्यक्ष श्री श्रीमत् पाण्डे ने बुधवार को वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा कृषि उपभोक्ताओं के लिए की गई घोषणाओं के क्रम में डिस्कॉम द्वारा जारी आदेशों को लागू करने की स्थिति, राजस्व वसूली एवं मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान के तहत लॉस रिडक्शन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कमजोर प्रदर्शन वाले अधिकारियों को निर्देश दिए कि निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएं। इसके साथ ही आज सरकारी विभागों पर बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए एक माह के लिए एमनेस्टी योजना भी लागू की गई है।

श्री पाण्डे ने मुख्यमंत्री विद्युत सुधार अभियान के तहत लॉस रिडक्शन की स्थिति की सर्किलवार जानकारी लेते हुए कहा कि सबने मिलकर कार्य किया है, जिससे अधिकांश सर्किलों में वितरण हानि को कम करने में सफलता मिलने के कारण स्थिति में सुधार आया है। इसके साथ ही मार्च माह में राजस्व वसूली के लिए भी विशेष प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे शत–प्रतिशत राजस्व वसूली के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। उन्होंने कहा कि कुछ जगहों पर अधिकारी पूरी निष्ठा से कार्य नही कर रहे हैं इस वजह से सुधार नही हो रहा है। ऐसे अधिकारियों को निर्देश दिए कि समय रहते कार्य प्रणाली में सुधार नही किया तो उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

डिस्कॉम अध्यक्ष ने बताया कि आज ही सरकारी विभागों पर बिजली की बकाया राशि की वसूली के लिए एमनेस्टी योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत 31 मार्च, 2017 तक केन्द्र/राज्य सरकार के विभागों द्वारा मूल बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर बकाया राशि पर देय एलपीएस/डीपीएस/ब्याज की पूरी छूट दी जाएगी। सभी अधिकारी इस योजना के तहत सरकारी विभागों पर बकाया राशि की वसूली के लिए भी प्रयास करे।

वीडियों कॉन्फ्रेंस में तीनों डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशकों ने डिस्कॉम स्तर पर लॉस रिडक्शन एवं राजस्व वसूली के लिए किए जा रहे प्रयासों से अवगत कराते हुए बताया कि जिन उपखण्डों में कमजोर स्थिति है वहां सुधार के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को लगा दिया गया है और उनकों बकाया राशि की वसूली के लिए जिम्मेदारी दी गई है। जयपुर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री ए.के.बोहरा ने बताया कि सभी सर्किलों में लॉस में कमी आना शुरु हो गया है एवं राजस्व वसूली में सुधार के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे है, जिनमें एटीवीस की टीम को एनडीएस एवं औधोगिक के बड़े उपभोक्ताओं की जांच के लिए और ओ एण्ड एम की टीम को बकाया की वसूली के लिए लगाया गया है। इसके साथ ही निगम स्तर पर प्रतिदिन नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है। जोधपुर डिस्कॉम की प्रबन्ध निदेशक आरती डोगरा ने बताया कि बीकानेर सिटी एवं जोधपुर जिला वृत के अलावा अन्य सर्किलों में सुधार आया है एवं सभी कृषि कनेक्शन भी जारी कर दिए है। अजमेर डिस्कॉम के प्रबन्ध निदेशक श्री एम.आर.विश्नोई ने बताया कि लॉस रिडक्शन प्रोग्राम के तहत कुछ सर्किलों में शेष कार्य को मार्च में पूरा कर लिया जाएगा एवं राजस्व वसूली के लिए भी इन सर्किलों में विशेष प्रयास किए जा रहे है।

वीडियों कॉन्फ्रेंस में तीनों डिस्कॉम के निदेशक तकनीकी, निदेशक वित्त, सचिव–प्रशासन, संभागीय मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता, अधिशाषी अभियन्ता अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

———

प्रेस विज्ञप्ति संख्या– 528/2017